13 मिनट में पार किए 45 लाख रुपए की चांदी के गहने

जयपुर (कासं)। सदर इलाके में अज्ञात नकबजन एक आभूषण कारखाने पर निशाना साधते हुए महज 13 मिनट में 45 लाख रुपए की चांदी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। वारदात कि जानकारी मिलने के बाद पीड़ित ने पुलिस की शरण ली। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने एफएसएल टीम की सहायता से घटना स्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाकर नकबजनों की तलाश शुरु कर दी है।

पुलिस ने बताया कि चांदपोल बाजार स्थित जाट के कुएं का रास्ता निवासी व्यापारी बलराम सोनी ने मामला दर्ज कराया है कि रेलवे स्टेशन रोड पर दिगंबर जैन मंदिर के पास उनका आभूषण निर्माण कारखाना है। जिसके पीछे जैन मंदिर स्थित है। अज्ञात नकबजनों ने मंदिर परिसर का ताला तोड़ा और वहां से कारखाने के अंदर घुसे। कारखाने के अंदर घुसने के बाद अज्ञात नकबजन काउंटर में रखी 20 किलो चांदी के आभूषण कट्टों और थैलों में भरकर ले गए।

अशलेश पंवार व मानसिंह को बधाई दी

जयपुर । सहकारिता विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारी अशलेश पंवार एवं मानसिंह शेखावत ने पांचवीं ओपन सेन्ट्रल एशियन हैण्डबॉल पुरूष चैम्पियनशिप में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने उन्हें इस उपलब्धि पर बधाई तथा शुभकामनाएं दी हैं। अशलेश पंवार एवं मानसिंह शेखावत ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन उज्बेकिस्तान के ताशकन्द में 31 मार्च से 5 अप्रेल तक किया गया था। प्रतियोगिता में विभिन्न देशों की कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया था।

जयपुर में यादगार से सांगानेर तक बनेगा मॉडल ट्रैफिक कॉरिडोर

देश के प्रमुख महानगरों की यातायात व्यवस्था का अध्ययन करके बनाई जयपुर की रूपरेखा

-कार्यालय संवाददाता-

- ट्रैफिक पुलिस की बदलेगी वर्दी, यातायात जाम की स्थिति का आंकलन करने के लिए ड्रोन का उपयोग भी किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री भजनलाल के निर्देश पर इस इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को चरणबद्ध रूप से राजधानी में लागू किया जाएगा।

जयपुर । राजधानी जयपुर में यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत ट्रैफिक पुलिस में ट्रैफिक इंस्पेक्टर से लेकर एडिशनल डीसीपी के पदों में बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता सुधार के लिए उनकी वर्दी बदलेगी। अभी व्हाइट रंग से बदलते हुए नए कलर की वर्दी दी जाएगी। ट्रैफिक पुलिस बेड़े के ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स को 20 मॉडिफाइड मोटरसाइकिलें मिलेंगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने देश के प्रमुख महानगरों की यातायात व्यवस्थाओं का अध्ययन एवं फील्ड विजिट करने के बाद समीक्षा कर व्यापक सुधार की रूपरेखा बनाई है। इस इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को चरणबद्ध रूप से शहर में लागू किया जाएगा। साथ ही अजमेरी गेट स्थित यादगार से सांगानेर तक मॉडल ट्रैफिक कॉरिडोर के रुप में विकसित किया जाएगा। ट्रैफिक की निगरानी एवं जाम की स्थिति का आंकलन करने के लिए ड्रोन का उपयोग भी किया जाएगा।

प्लान के तहत शुरुआती चरण में टोंक रोड को यादगार से सांगानेर तक मॉडल ट्रैफिक कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। इस कॉरिडोर पर नगर निगम और जेडीए के कॉर्डिनेशन से अलग-अलग काम करवाए जाएंगे।

इसमें सड़क डिजाइन में आवश्यक सुधार करते हुए असुरक्षित कट्स (मीडियन ओपनिंग) को बंद किया जाएगा। पैदल यात्रियों के लिए सेफ फुटपाथ का निर्माण, यू-टर्न और क्रॉसिंग पॉइंट्स का टेक्निकली कार्य शामिल किए जाएंगे। ट्रैफिक सिग्नल की टाइमिंग को भी रीयल टाइम यातायात दबाव के अनुसार डायनेमिक बनाया जाएगा।

ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स को मिलेंगी 20 बाइक

जयपुर ट्रैफिक पुलिस के बेड़े में 20 मॉडिफाइड मोटरसाइकिलें भी शामिल होंगी। यह मोटरसाइकिल ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स को मिलेंगी। इन्हें विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इससे ट्रैफिक इंस्पेक्टर भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में तेज मूवमेंट कर सकेंगे। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग भी बढ़ाया जाएगा। इसमें अभय कमांड सेंटर से जुड़े अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरों की स्थापना शामिल है। इससे रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी।

72 ट्रैफिक बीट में बंटेगी जिम्मेदारी

जयपुर शहर को 72 ट्रैफिक बीट्स में विभाजित करने से प्रत्येक क्षेत्र में स्पष्ट जिम्मेदारी निर्धारित हो सकेगी। प्रत्येक बीट में कार्मिकों की संख्या बढ़ाने के साथ ही उनकी तैनाती को तर्कसंगत बनाया जाएगा। इससे पीक ऑवर्स में प्रभावी यातायात नियंत्रण एवं त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित होगी। यातायात प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए बीट स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एवं जवाबदेही की प्रणाली विकसित होगी।

ट्रैफिक पुलिस में अफसरों के पदों की संख्या बढ़ाई

नए प्लान के तहत ट्रैफिक पुलिस के प्रशासनिक ढांचे में भी बदलाव होगा। अब जयपुर शहर में अब एडीसीपी (ट्रैफिक) के पदों की संख्या 2 से बढ़ाकर 4 करने से जयपुर शहर के प्रत्येक पुलिस जिले में एक-एक एडीसीपी (ट्रैफिक) की तैनाती सुनिश्चित होगी। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आएगी तथा बेहतर निरीक्षण संभव होगा।

इसी प्रकार एसीपी (ट्रैफिक) के पदों की संख्या भी 4 से बढ़ाकर 8 करने से प्रत्येक पुलिस जिले में 2 एसीपी (ट्रैफिक) नियुक्त किए जाएंगे। इससे निगरानी, प्रवर्तन एवं समन्वय का कार्य अधिक प्रभावी ढंग से संचालित हो सकेगा। वहीं, ट्रैफिक इंस्पेक्टर (टीआई) की संख्या 15 से बढ़ाकर 20 करने से प्रत्येक पुलिस जिले में औसतन 5 टीआई की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इससे स्थानीय स्तर पर जवाबदेही एवं नियंत्रण में सुधार हो पाएगा।

4 अति. पुलिस उपायुक्तों को ट्रैफिक मैनजमेंट का जिम्मा

जयपुर । राज्य सरकार के गृह विभाग ने सोमवार को एक आदेश जारी कर पुलिस बेड़े में प्रशासनिक फेरबदल किया है। जारी इन आदेशों के तहत जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में चार अतिरिक्त पुलिस उपायुक्तों (एडीसीपी) के स्थानांतरण और पदस्थापन किए गए हैं। इस बदलाव का मुख्य केंद्र यातायात शाखा और मुख्यालय उत्तर रहे हैं।वरिष्ठ शासन उप सचिव (पुलिस) रत्नेश कुमार शर्मा द्वारा जारी इन आदेशों के अनुसार एसओजी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत हरिप्रसाद सोमानी को अब अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात (उत्तर) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चतुर्थ बटालियन आरएसी के कमांडेंट समीर कुमार को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, यातायात (पश्चिम) के पद पर तैनात किया गया है। पीसीपीएनडीटी इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. हेमन्त कुमार जाखड़ अब अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, यातायात (पूर्व) के रूप में कार्यभार संभालेंगे औरयातायात शाखा (उत्तर) में कार्यरत सरिता बड़गुर्जर का तबादला कर उन्हें अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय-उत्तर) पुलिस आयुक्तालय जयपुर के पद पर नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ शासन उप सचिव (पुलिस) रत्नेश कुमार शर्मा द्वारा जारी इन आदेशों में सभी अधिकारियों को अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर तुरंत प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि इस फेरबदल से शहर की यातायात व्यवस्था और प्रशासनिक कामकाज में नई ऊर्जा देखने को मिलेगी।

''राजस्थान यूथ डायलॉग'' में मुख्यमंत्री ने किया संवाद

युवा शक्ति ही देश की दिशा तय करेगी : भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 'माय भारत बजट क्वेस्ट-राजस्थान यूथ डायलॉग'' कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से प्रतिभागियों से संवाद किया।

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी पूंजी हैं और वही देश की दशा और दिशा तय करते हैं। उन्होंने युवाओं से अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करने का आव्हान करते हुए भरोसा दिलाया कि सरकार उनके हर कदम पर साथ खड़ी है।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 'माय भारत बजट क्वेस्ट-राजस्थान यूथ डायलॉग'' कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से प्रतिभागियों से संवाद किया। इस दौरान युवाओं ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और युवा नीति लागू करने जैसे निर्णयों के लिए सरकार का आभार जताया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 75 हजार से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें राज्य के युवाओं ने अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार ने 4 लाख भर्तियों के लक्ष्य के तहत अब तक एक लाख 25 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है, जबकि निजी क्षेत्र में 3 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

पेपर लीक जैसे मामलों पर सख्ती दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने जांच के लिए एसआईटी गठित कर 420 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले दो वर्षों में 351 से अधिक परीक्षाएं बिना किसी पेपर लीक के पारदर्शी तरीके से करवाई हैं।

जामडोली से लापता 14 वर्षीय बालक ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया के नीचे मिला

विभिन्न बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक स्थलों पर सघन तलाशी अभियान चलाया। साथ ही तकनीकी सहायता और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बालक की लोकेशन ट्रेस की गई। पुलिस टीम की कड़ी मेहनत के बाद बालक विक्रांत को दिल्ली बाईपास रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया के नीचे से सकुशल ढूंढ निकाला। पूछताछ में सामने आया कि बालक अपनी स्वेच्छा से घर छोड़कर गया था और उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी या अपराध घटित होना नहीं पाया गया है।

जयपुर (कासं)। राजधानी की जामडोली थाना पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए तीन दिन से लापता एक नाबालिग बालक को सुरक्षित दस्तयाब कर उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। जिससे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई।

पुलिस उपायुक्त (पूर्व) रंजिता शर्मा ने बताया कि सुमेल (जामडोली) निवासी 14 वर्षीय बालक विक्रांत बुनकर पुत्र बनवारी लाल बुनकर गत 9 अप्रैल को अपने घर से बिना बताए कहीं निकल गया था। परिजनों की रिपोर्ट पर थाना जामडोली में अपहरण की धाराओं (137 (2) बीएनएस) में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सहायक पुलिस आयुक्त (आदर्श नगर) लक्ष्मी सुथार के सुपरविजन में थानाधिकारी रतन सिंह कविया के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने शहर के

'मई-जून में गर्मी पडेगी और बाद में बारिश होगी, इसलिए फिलहाल चुनाव नहीं करवा सकते'

पंचायत और निकाय चुनाव की तारीख आगे बढ़वाने के लिए हाईकोर्ट पहुंची राज्य सरकार

-कार्यालय संवाददाता-

- अदालत में दायर प्रार्थना पत्र में राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि ''ओबीसी आयोग की रिपोर्ट 30 सितंबर तक आने की संभावना है। इसके बाद आरक्षण तय कर तुरंत चुनाव अधिसूचित कर दिए जाएंगे।''

जयपुर । प्रदेश में पंचायत व निकाय चुनाव में देरी से जुड़े मामले में राज्य सरकार ने अब चुनाव कराने की तिथि को बढ़ावाने के लिए हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया है। इसमें राज्य सरकार ने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में आगामी महीनों में चुनाव करना संभव नहीं है। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि, मई-जून में गर्मी पडेगी और बाद में बारिश होगी, इसलिए फिलहाल चुनाव नहीं करवा सकते।

महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद की ओर से पेश प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि अभी तक ओबीसी आरक्षण का निर्धारण नहीं हो पाया है और संविधान के अनुच्छेद 243-डी एवं 243-टी के तहत स्थानीय निकायों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण देने का प्रावधान है। इसलिए राज्य में पंचायत व निकाय चुनाव अभी नहीं हो सकते। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट 30 सितंबर तक आने की संभावना है। ऐसे में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिलते ही आरक्षण तय कर तुरंत चुनाव अधिसूचित कर दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने यह प्रार्थना पत्र पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और गिर्राज देवंदा की जनहित याचिकाओं में दायर किया है।

राज्य सरकार ने कहा कि स्थानीय निकायों के लिए करीब 1.26 लाख और ग्रामीण पंचायती संस्थाओं के लिए करीब 2.50 लाख मतदान कर्मचारियों की जरूरत होगी। इनमें करीब 70 फीसदी शिक्षाकर्मी रहेंगे। फिलहाल स्कूलों में 1 अप्रैल 2026 से शैक्षिणक शुरू हो चुका है और मई-जून में प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू चलने की संभावना है। वहीं जुलाई से सितंबर तक मानसून और कृषि कार्यों में आमजन व्यस्त रहेगा।

इस दौरान चुनाव कराना न तो कर्मचारियों, उम्मीदवारों और मतदाताओं के स्वास्थ्य के लिए उचित है और न ही व्यावहारिक। वहीं कई पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल सितंबर से दिसंबर 2026 में खत्म होगा। राज्य चुनाव आयोग को चुनाव अधिसूचना जारी करने और प्रक्रिया पूरी करने में कम से कम तीन महीने का समय लगेगा। इसलिए चुनाव कराने के लिए समय दिया जाए।

मामले से जुड़े अधिवक्ता प्रेमचन्द देवन्दा ने बताया कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने गिरिराज सिंह की याचिका मंजूर कर 14 नवंबर 2025 को प्रदेश की पंचायतों और स्थानीय निकाय चुनाव 15 अप्रैल तक करवाने के लिए राज्य सरकार व निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए थे, लेकिन राज्य सरकार ने आदेश की पालना नहीं की और अब चुनाव का समय बढवाने के लिए हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया है।

अनसेफ पाए जाने पर 17 खाद्य उत्पाद प्रतिबंधित

प्रदेशभर में वितरण, विक्रय और डिस्पले पर दो माह तक रोक

जयपुर । खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय ने मिलावटी 17 खाद्य उत्पादों को प्रदेशभर में 2 माह तक प्रतिबंधित कर दिया है। राज्य में इनके वितरण, विक्रय और डिस्पले पर रोक लगा दी गई है। पिछले दिनों विभाग ने इन तमाम सामग्रियों के सैंपल लिए थे, जो कि जांच में अनसेफ पाए गए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि युवराज बीकानेर ब्रांड की केसर बाटी, बंगाल गोल्ड ब्रांड की चाय, शुगर बॉयल्ड कंफेक्शनरी ''नगद नारायण'' तथा श्री डेयरी प्रीत, हरियाणा और श्री डेयरी ब्राइट ब्रांड का घी, श्री साई मसालेवाला ब्रांड की हल्दी, धेनु सरस ब्रांड घी, ईजी डेयरी ब्रांड घी, भोग विनायक घी, ब्रांड स्नेक टेक का रोस्टेड चना, हरियाणा क्रीम ब्रांड घी, श्री भैरव सरस घी, जयश्री कृष्णा घी, डेयरी पंजाब घी तथा बालाजी ब्रांड का तीखा मीठा मिक्स नमकीन खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में असुरक्षित प ा ा गए है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि खाद्य व्यापारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 46(4) की निर्धारित अवधि में पुन: जांच के लिए अपील करने के बाद रेफ़रल प्रयोगशाला की रिपोर्ट अनसेफ प्राप्त होने या धारा 46(4) की अवधि में अपील नहीं करने पर इन खाद्य पदार्थों के रिकॉल की प्रकिया अमल में लाई जाएगी।

अत: आमजन को सलाह दी गई है कि वे इन खाद्य पदार्थों की खरीद और उपयोग नहीं करें। अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह ने बताया कि जिन उत्पादों का निर्माण दूसरे राज्यों में हो रहा है, उन राज्यों में स्थापित निर्माण इकाइयों या कम्पनियों पर एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए वहां के खाद्य सुरक्षा विभाग को पत्र लिखा गया है।

विधानसभा को आर.डी.एक्स. से उडाने की धमकी से हड़कंप मचा

सुरक्षा एजेंसियों, डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते ने विधानसभा परिसर के चप्पे-चप्पे की तलाश ली, जांच में विस्फोटक अथवा संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर राहत की सांस ली

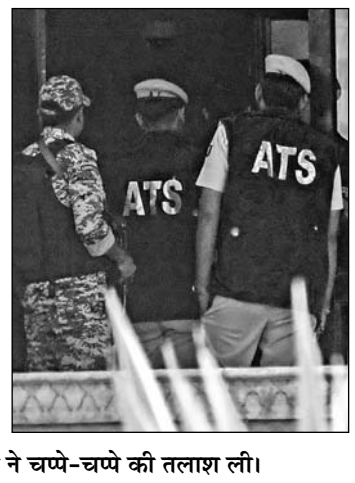

राजस्थान विधानसभा को आरडीएक्स से उडाने की धमकी मिलने की सूचना के सुरक्षा एजेंसियों, पुलिस और डॉग स्क्वॉड ने चप्पे-चप्पे की तलाश ली।

जयपुर (कासं)। राजस्थान विधानसभा को आरडीएक्स से उडाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद सोमवार को हड़कंप मच गया, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की सघन जांच में यह धमकी पूरी तरह फर्जी पाई गई।

इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत राज्य के पुलिस महानिदेशक को सूचना दी और पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए रखी। एहतियातन विधानसभा परिसर को खाली कराया गया, जिसके बाद बम निरोधक दस्ते और विशेष पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर व्यापक तलाशी अभियान चलाया।

- ई-मेल भेजने वालों की तलाश में जुटी है साइबर एजेंसियां,अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी

एंटी सबोटाज चेक टीम द्वारा आधुनिक उपकरणों की सहायता से विधानसभा परिसर की गहन जांच की गई। जांच के दौरान किसी भी प्रकार का विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर सुरक्षा एजेंसियों ने स्थिति को पूरी तरह सुरक्षित बताया और प्रमाण-पत्र भी जारी किया।

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि ईमेल की सामग्री भ्रामक और असंबंधित है, जिसका विधानसभा से कोई लेना-देना नहीं है। ईमेल में कुछ तथ्यहीन और भटकाने वाली बातें लिखी गई थीं, जिन्हें गंभीरता से लेते हुए साइबर एजेंसियों द्वारा स्त्रोत का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने विधानसभा अधिकारियों और कर्मचारियों से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए उनका मनोबल भी बढ़ाया। जांच पूरी होने के बाद विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी पुन: अपने कार्यस्थलों पर लौट आए और परिसर में सामान्य कामकाज बहाल हो गया।

हाईकोर्ट और जिला न्यायालय में भी बम विस्फोट की धमकी

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट और जिला न्यायालय में बम विस्फोट करने की धमकी के साथ सोमवार को कोर्ट की आधिकारिक मेल आइडी पर ईमेल भेजे गए। हालांकि हर बार की तरह पुलिस को तलाशी में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला और यह सिर्फ धमकी निकली।

जानकारी के अनुसार ग्रीष्मकालीन कोर्ट के पहले दिन सुबह जिला न्यायालय की ऑफिशियल मेल आईडी पर यह धमकी भरा ईमेल भेजा गया। इस पर कोर्ट प्रशासन की ओर से स्थानीय थाने सहित आलाधिकारियों को जानकारी दी गई। इसके बाद कोर्ट परिसर को खाली कराया गया। इस दौरान हाईकोर्ट प्रशासन को भी धमकी भरा ईमेल भेजा गया। ऐसे में हाईकोर्ट परिसर की भी तलाशी ली गई। दोनों कोर्ट परिसर में पुलिस की विभिन्न एजेंसियों के आलाधिकारी और डॉग स्वायड भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान डॉग स्वायड ने कोर्ट परिसर के चप्पे-चप्पे की तलाशी ली, लेकिन कहीं कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी सेशन कोर्ट परिसर में करीब आधा दर्जन बार बम विस्फोट करने की धमकी देते हुए ईमेल भेजे गए हैं। वहीं हाईकोर्ट में सिरफिरों ने एक दर्जन से अधिक बार ऐसे मेल भेजे हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा का कहना है कि हर बार मेल मिलने के बाद जांच एजेंसियां आकर परिसर की तलाशी लेती हैं, लेकिन यह सिर्फ धमकी ही साबित होती है। इस दौरान सरकार के लाखों रुपए भी खर्च होते हैं।

एयरपोर्ट से हल्दी घाटी सर्किल की 100 फीट चौडी रोड के निर्माण का आदेश वापस लिया हाईकोर्ट ने

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट से प्रताप नगर के हल्दी घाटी सर्किल तक की 100 फीट चौडी रोड के निर्माण के संबंध में छह माह पहले दिए अपने आदेश को वापस ले लिया है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित ने यह आदेश अजय मार्ग निर्माण संघर्ष समिति व अन्य की ओर से दायर याचिका में दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए।

रमेश चन्द्र मीणा व अन्य की ओर से अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने अदालत को बताया कि खंडपीठ ने जेडीए को निर्देश दिए थे कि साल 2011 के सेक्टर प्लान के अनुसार तय अलाइनमेंट के अनुसार रोड निर्माण किया जाए। वहीं रोड का जो हिस्सा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड व जयपुर नगर निगम के क्षेत्राधिकार में है, उसके निर्माण का खर्चा हाउसिंग बोर्ड व नगर निगम से वसूला जाए। यदि उनसे खर्चा नहीं मिले तो राज्य सरकार अपने खर्चे पर ही रोड का निर्माण करे, केवल खर्चे के आधार पर ही रोड का निर्माण कार्य नहीं रोका जाए। इसके अलावा खंडपीठ ने कहा था कि यदि इस रोड के संबंध में किसी भी कोर्ट में कोई स्टे चल रहा है तो वह इस आदेश में ही समाहित हो जाएगा।

वहीं इस रोड के निर्माण कार्य के संबंध में कोई भी ट्रिब्यूनल या कोर्ट किसी के दावे को मंजूर नहीं करे। इसके अलावा रोड के निर्माण के दौरान चाहें तो पुलिस की मदद भी ली जा सकती है। अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने अदालत को कहा कि एक्टिंग सीजे बतौर वकील इस याचिका में पैरवी कर चुके हैं। ऐसे में उनकी ओर से मामले की सुनवाई करना उचित नहीं था। अदालत की ओर से आदेश देने के बाद उन्हें इस संबंध में जानकारी मिली है। ऐसे में खंडपीठ इस आदेश को वापस ले।

जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने आदेश वापस लेते हुए इसकी सुनवाई दूसरी खंडपीठ को करने को कहा है। याचिका में कहा था कि सेक्टर प्लान में यह रोड 100 फीट की है, लेकिन कई सालों से इस रोड का निर्माण नहीं हो पा रहा है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के कारण ही हाउसिंग बोर्ड सेक्टर एक व दो को आज तक विकसित नहीं कर पाया है। इसलिए रोड का निर्माण कराया जाए।

शातिर नटवरलाल से पुलिस ने 90 लाख रु. बरामद किए

जयपुर। मुरलीपुरा पुलिस ने शातिर ठगों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए 90 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में शत-प्रतिशत राशि बरामद कर ली है। इनकम टैक्स रेड का खौफ दिखाकर लूटीं गई राशि की बरामदगी के लिए पुलिस ने आरोपी के पैतृक आवास तक दबिश दी।

डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि आरोपी बाबूलाल वर्मा उर्फ बी.एल. गोयल को गिरफ्तार करने के बाद उसे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया था। कड़ाई से पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने ठगी की शेष राशि अपने मूल निवास चूरू में छिपा रखी है। इस सूचना पर पुलिस टीम ने चूरू स्थित उसके घर पर दबिश देकर 12 लाख 50 हजार रुपये और बरामद किए। अनुसंधान में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि आरोपी ने ठगी की राशि का उपयोग अपना पुराना कर्ज चुकाने में किया था। उसने केनरा बैंक (झुंझुनू) में अपने गोल्ड लोन की अदायगी के लिए 25 लाख रुपये जमा करवाए थे।